E-Newsletter
June 2016

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

LSG
Local Self Government
Rajasthan

Minimum Government, Maximum Governance

सत्यमेव जयते

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Local Self Government Rajasthan

The Department of local self Government, Rajasthan is the controlling Department of all municipalities for all administrative purposes. It also performs monitoring and co-ordination function at the state level for all the 188 municipal bodies of the state.

Functions of Department of Local Self Government Rajasthan

Appointment of OICs/Advocate in Court Cases, vetting of reply, opinion on judgment, decision for appeal or no appeal, scrutiny of Bye-Laws and Rules and Amendments in Acts and Rules.

Approval of Budget of ULBs and released of funds regarding Special Grant, General Grant, SFC, TFC, Grant (in Lieu of Octroi) and State/Centrally Sponsored Schemes/Programme.

Disposal of matters related to transfer, establishment, DPCs related to officers and staff of ULBs, DDR offices and Directorate.

Extension and Exclusion of Municipal boundary, Election of Municipal Boards.

Implementation of HRD Plan for elected representatives, and officials of ULBs.

Implementation of Poverty Alleviation and social responsibilities Programmes.

Issuance of Financial, Administrative and Technical Sanctions which are not in the Jurisdiction of the elected board.

Preparation of Annual Plan/District Plan/Action Plan/DPRs related to various GoI/GoR schemes/Programmes.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Various Schemes

AMRUT – (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Urban Infrastructure Development of 29 Towns > 1.0 lac population.

Total Estimated Project cost Rs 4500 cr (50% GoI, 30% GoR, 20% ULB)

Components to be covered - Water supply, Sewerage network, Septage management, Storm water drainage, Urban Transport, Green spaces and parks.

HRIDAY-Heritage Cities Infrastructure Development & Augmentation

- Ajmer – Pushkar nominated under HRIDAY– 100% grant by GoI.
- City HRIDAY Plan for Rs 48.00 cr. approved by MoUD, GoI.

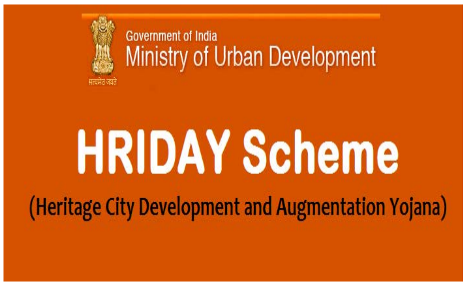

National Urban Livelihood Mission (NULM)

- Focus on Skill Training & Placement and Capacity Building / Self Employment.
- Major components- Shelter for Urban Homeless, Support to Urban Street Vendors.

National Urban Livelihoods Mission
SHAPING THE FUTURE

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्मार्टराज कॉल सेन्टर

आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास ....

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है जिसमें आईवीआर नं0 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर दर्ज की जा रही है। 11 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक 109588 कॉल प्राप्त हुई एवं 8600 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 5894 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों/निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित है, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत/निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

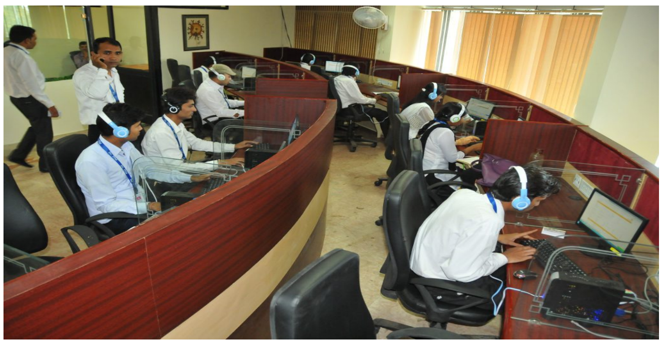

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान ....

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शोच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।

इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ''स्वच्छ राजस्थान अभियान'' चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पार्को की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वाड़ सभाऐं, नुक्कड नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छत्ता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए. आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015–16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाने के लिए दो दिवसीय ''हैण्ड होल्डिंग'' कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' सम्बन्धित शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होनें कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होने बताया कि अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का ''सिटी लेवल सर्विस इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाकर तद्नुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रथम वर्षगांठ–मुख्यमंत्री ने की स्मार्ट जयपुर के लिए सौगातों की बरसात

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई सौगातें दी। श्रीमती राजे ने रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने, बस शैल्टर्स में पब्लिक इन्फोरमेशन सिस्टम एवं रामनिवास बाग में नवीनीकृत सावन भादो उद्यान का उद्घाटन किया। उन्होंने गुलाबी नगर की 14 बावड़ियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया। श्रीमती राजे ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश से चयनित शहरों पर ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों में हैरिटेज, पर्यटन, स्मार्ट नगरीय ढांचे एवं सुरक्षित सड़क ढांचे का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब जयपुर प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देश का अव्वल शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हम स्वच्छ भारत मिशन में भी देश में सबसे आगे हैं। प्रदेश में बीकानेर पहला खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) जिला बन चुका है। इस तरह प्रदेश के 7 जिले ओडीएफ बनने की कतार में हैं। हैरिटेज स्वरूप बनाए रखते हुए करें विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में विकास कार्यो में यह ध्यान रखा जाए कि हैरिटेज स्वरूप को बनाए रखते हुए जयपुर को आधुनिक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि परकोटे में इमारतों के बाहरी स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। पर्यटक हमारी पिंकसिटी की पुरानी खूबसूरती को देखने आते हैं न कि कांच की इमारतों को। परकोटा वासियों से अपील, छतों पर सोलर प्लांट लगाएं श्रीमती राजे ने कहा कि जयपुर में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकारी इमारतों के छत पर रूफ टॉप सॉलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। झालाना संस्थानिक क्षेत्र और जेएलएन मार्ग पर स्थित सभी सरकारी इमारतों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने चारदीवारी क्षेत्र के निवासियों का आह्वान किया कि वे अपने घरों की छत पर रूफ टॉप सॉलर प्लांट लगाएं ताकि परकोटा क्षेत्र को बेतरतीब फैले बिजली के तारों के जाल से मुक्त कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर में जगह– जगह बिजली और केबल के तार नहीं दिखेंगे तो इसकी खूबसूरती और निखरेगी। साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पर खर्च में भी कमी आएगी। शहर को साफ रखना हम सबका फर्ज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर को साफ–सुथरा और सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर निभानी होगी। शहर में सड़कों पर या पार्कों पर जहां भी पॉलिथीन उड़ती दिखें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उठाकर कचरा पात्र में डालें। उन्होंने कहा कि जब मैं स्वयं सड़क पर कचरा देखकर अपनी कार रूकवाकर उसे साफ करवाती हूं तो आप भी इसी भावना से कार्य करते हुए अपना दायित्व निभाएं। श्रीमती राजे ने कहा कि शहर की कॉलोनियों में बने छोटे पार्कों की सार–संभाल के लिए विकास समितियों को आगे आना चाहिए। रामनिवास बाग में सावन–भादों पार्क के अलावा करीब 10 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर टिकट राजस्व वसूली के लिए नहीं बल्कि वहां साफ–सफाई एवं सुविधाओं के विकास के लिए लगाया जाता है। सड़कों पर नहीं छोड़ें पालतू पशु मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गोपालकों से अपील की कि वे अपनी पालतू गायें एवं अन्य पशु खुले में सड़क पर नहीं छोड़ें। इससे गन्दगी तो फैलती ही है साथ ही यातायात भी बाधित होता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि आवारा पशु सड़कों पर नहीं घूमें और सड़कों पर पशु छोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने इसके लिए बड़ा जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को मिले सख्त सजा श्रीमती राजे ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले कुंठाग्रस्त लोगों के साथ सख्ती से पेश आएं। उन्होंने कहा कि पुलिस और न्यायिक अधिकारी इस तरह के मामलों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था बनाने के बारे में सोचें ताकि ऐसे अपराधों के दोषियों को जल्द सजा मिल सके। अम्बेडकर सर्किल के पास गाड़ी रूकवाकर कचरा हटवाया मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री निवास आते समय अम्बेडकर सर्किल के पास सड़क पर कचरा देखकर अपनी गाड़ी रूकवाई और सुरक्षाकर्मियों को अविलम्ब कचरा हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पास ही स्थित जीवन बीमा निगम की

इमारत के सुरक्षाकर्मी को निर्देश देकर भवन के प्रवेश द्वार पर बिखरा कचरा हटवाया। स्मार्ट राजस्थान की दिशा में काम स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। पानी की उपयोगिता व संरक्षण के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का असर दिखने लगा है। अब सरकार स्मार्ट राजस्थान की दिशा में तेजी से काम कर रही है। महापौर श्री निर्मल नाहटा ने कहा कि जयपुर की कला–संस्कृति और हेरिटेज पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हमारा लक्ष्य यहां की प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए शहर को स्मार्ट बनाना है। इससे पूर्व जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी. सरवन कुमार ने जयपुर स्मार्ट सिटी के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यक्रम के अंत में जयपुर नगर निगम के आयुक्त श्री हेमन्त कुमार गेरा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस तरह बनेगा जयपुर स्मार्ट शहर प्रमुख घोषणाएं– श्रीमती राजे ने इस अवसर पर जयपुर शहर के लिए इन परियोजनाओं की घोषणा की।

लांगरियावास में 180 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी आधार पर कचरे से बिजली बनाने का प्लांट।

46.23 करोड़ रुपये की लागत से 100 नई सिटी बसों की खरीद।

बगराना में जेसीटीएसएल का एकीकृत वर्कशॉप कम बस डिपो। इस डिपो पर 16.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

स्मार्ट सिटी क्षेत्र के लिए ये प्रस्ताव भी

सस्टेनेबल मोबिलिटी कोरिडोर– पैदल और साइकिल यात्रियों, दिव्यांगों एवं मोटर वाहन चालकों के लिए 132 करोड़ रुपये की लागत से सस्टेनेबल मोबिलिटी कोरिडोर।

हैरिटेज एवं पर्यटन– जलेबी चौक, टाउन हॉल एवं पुराने पुलिस मुख्यालय जैसी हैरिटेज इमारतों का बेहतर रख–रखाव कर इनका उचित उपयोग किया जाएगा।

स्मार्ट नगरीय ढांचा– 433 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ये काम किए जाएंगे।

– सरकारी इमारतों, स्मारकों एवं पार्कों में वेस्ट वाटर का पुनर्चक्रण एवं वर्षा जल संरक्षण। – स्मार्ट मीटर के माध्यम से प्रभावी जल प्रबन्धन। – ऑटोमेटेड ऑन लाइन रेसिडुअल क्लोरिन मोनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जायेगा। – ठोस कचरे का स्मार्ट कलेक्शन। – नागरिकों की सुरक्षा के लिए वीडियो क्राइम मोनिटरिंग, इन्सीडेंट अलर्ट एप, हैल्प लाइन, पैनिक बटन। – जीआईएस आधारित प्रोपर्टी इन्वेटरी तथा सम्पत्ति कर की ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था। – हवा की गुणवत्ता एवं मौसम की मोनिटरिंग के लिए एप। – यातायात नियमों के उल्लंघन, ठोस कचरे के निस्तारण जैसी समस्याओं के लिए मोबाइल एप। पूरे शहर के लिए ये प्रस्ताव

यातायात के एक से अधिक साधनों का उपयोग करने के लिए स्मार्ट मोबिलिटी के तहत ओपन स्टैण्डर्डस बेस्ड फेयर कार्ड एवं टिकटिंग प्रणाली

जयपुर मल्टी मोडल पब्लिक ट्रांजिट सेंट्रल ऑपरेशन्स एण्ड मैनेजमेंट सेंटर

पब्लिक इनफॉरमेशन एवं यात्रा प्लानिंग

स्मार्ट ठोस कचरा प्रबन्धन

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में स्मार्ट सिटी की प्रगति का ब्यौरा दिया प्रधानमंत्री ने जयपुर और उदयपुर वासियों को स्मार्ट सिटी में चयनित होने के लिए बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य शुरू होने के अवसर पर जयपुर और उदयपुर शहरवासियों को स्मार्ट सिटी में चयनित होने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा का एक वर्ष पूरा होने पर पुणे के छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर और उदयपुर के चयन के लिए धन्यवाद के असली हकदार यहां के निवासी हैं। इन लोगों के प्रयासों के कारण ही स्मार्ट सिटी प्रतिस्पर्धा के सभी पेरामीटर्स को समय सीमा में पूरा कराया जा सका और इन दोनों शहरों को प्रतिस्पर्धा में जीत के साथ पहले चरण के 20 शहरों में चुना गया। इससे पहले मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राजस्थान से जयपुर एवं उदयपुर को इस मिशन के प्रथम चरण में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। श्रीमती राजे ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जयपुर में आज रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने, बस शैल्टर्स में पब्लिक इन्फोरमेशन सिस्टम एवं रामनिवास बाग में नवीनीकृत सावन भादो उद्यान का शुभारम्भ किया गया। साथ ही, शहर की 14 बावड़ियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर दक्षिण एशिया के पहले लाइटहाउस सिटी के लिए चुना गया है। इससे पिंकसिटी जयपुर हेम्बर्ग, बार्सिलोना और एडिलेड जैसे शहरों की सूची में शामिल हो गया है। श्रीमती राजे ने कहा कि सिस्को की साझेदारी से शहर में वाई—फाई हॉटस्पॉट, वीडियो सर्वेलांस कैमरा, इन्टरेक्टिव कियॉस्क, रिमोट ई—गवर्नेंस समाधान एवं पार्किंग मैनेजमेंट प्रणालियों की आईटी आधारित कई सेवाओं की शुरूआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर में कचरे से बिजली बनाने के लिए पीपीपी आधार पर प्लांट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर में धरोहर संरक्षण एवं विकास के कार्य, स्मार्ट क्लास रूम्स, रूफ टॉप सोलर प्लांट की स्थापना और कमान्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर विकसित करने और सीवरेज के कार्य हाथ में लिए गए हैं। श्रीमती राजे ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण के लिए अजमेर और कोटा के प्रस्ताव भी तय समय से पहले केन्द्र सरकार के पास भिजवा दिए जायेंगे।

अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी की प्रथम वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दिए निर्देश

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) एवं स्मार्ट सिटी की प्रथम वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने के लिए निर्देश केन्द्रिय शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री नीरज मण्डलोई व निदेशक श्री शिवपाल सिंह ने विडियों कांफ्रेंस मे दिये।

केन्द्रिय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नीरज मण्डलोई ने विडियों कांफ्रेंस में निर्देश दिये कि अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत जिन कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है एवं उनके कांट्रेक्टर निर्धारित हो चुके है। उन परियोजना का शिलान्यास/भूमि पुजन संबंधित नगर पालिका के अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों एवं निकाय अधिकारी की उपस्थिति में किया जाये।

उन्होनें यह निर्देश भी दिये कि 25 जून को अपराह्न 04:00 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूना में अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) का शुभारम्भ करेंगे। उक्त कार्यक्रम को प्रदेश की सभी 29 अमृत योजना की नगरीय निकायों में बड़ी स्क्रीन शहर के मुख्य स्थल/ऑडिटोरियम/सभागार में लगाकर नगर पालिका के अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों एवं निकाय अधिकारी को दिखाया जावे।

केन्द्रिय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नीरज मण्डलोई ने बताया कि अमृत मिशन में चयनित नगर निगम/परिषद में अमृत योजना, शहरी सुधार/शहरी योजना की जानकारी देने के लिए आधे दिन की कार्यशाला/कांफ्रेंस निकाय के अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, पार्षद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों एवं निकाय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की जाये।

उन्होनें यह निर्देश भी दिये कि 24 व 25 जून को इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से अमृत योजना की जानकारी आमजन को देकर प्रचार–प्रसार किया जाये तथा इस अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में अमृत योजना का लोगों आवश्यक रूप से लगाया जाये एवं आयोजित शिलान्यास/भूमि पूजन समारोह की फोटाग्राफी/विडियोग्राफी तथा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर

केन्द्र सरकार को रूडसिको (Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage & Infrastructure Corporation Limited) के माध्यम से भिजवाया जाये।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अमृत योजना के तहत अब तक सीवरेज की तीन परियोजनाओं अलवर 91 करोड़, भीवाड़ी 143 करोड़, सीकर 121 करोड़ के कार्यादेश L&T को दिये जाकर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में 7 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य प्रगति पर है। अब तक उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त लगभग 1000 करोड़ रूपये कि विभिन्न परियोजनाओं की निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है। जिनका आगामी एक माह में आदेश जारी किया जायेगा। यह परियोजनाएं मुख्य रूप से भरतपुर, हिण्डौन, गंगापुर सिटी, ब्यावर, सुजानगढ़, चुरू, चित्तौड़गढ़, नागौर, बून्दी, उदयपुर, जोधपुर, बारां में प्रारम्भ होगी।

राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी योजनाओ की समीक्षा

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने बुधवार को दोपहर 02:00 बजे स्वायत्त शासन भवन में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास परियोजना (आईएचएसडीपी), गरीबों के लिए बुनियादी सेवा योजना (बीएसयूपी) की समीक्षा की।

बैठक में डॉ मनजीत सिंह ने कि राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास परियोजना (आईएचएसडीपी), गरीबों के लिए बुनियादी सेवा योजना (बीएसयूपी) की समीक्षा की। उन्होनें निर्देश दिये कि एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास परियोजना (आईएचएसडीपी), गरीबों के लिए बुनियादी सेवा योजना (बीएसयूपी) योजनाओं के पूरा होने का समय 2017 है। अतः उक्त योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाये।योजनाओं में शेष कार्य यदि किसी कारण से पूरे नही हो सकते है, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित नगरीय निकाय प्राप्त पैसा ब्याज सहित 15 दिवस में रूडसिको को लौटाये। बैठक में राजीव आवास योजना की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया कि योजना के तहत कार्य पूर्णता की तिथि दिसम्बर 2017 है। अतः उक्त तिथि तक सभी कार्यो को पूर्ण करें।

बैठक में प्रधानमंत्राी आवास योजना एवं मुख्यमंत्राी जन आवास योजना की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकायो को निर्देश दिये गये कि वे कम से कम समय में एक–एक योजना अपने–अपने क्षेत्राों में विभिन्न प्रावधानों के बनाकर कार्य प्रारम्भ करें। उन्होने बैठक में यह निर्देश भी दिये कि उपरोक्त आवासीय योजनाओं के तहत जिन नगरीय निकायों में मकान बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वे शीघ्रतिशीघ्र लाभार्थियों को कब्जा देने का कार्य प्रारम्भ करें।

डॉ. मनजीत सिंह ने रूडसिको के अधिकारियों को निर्देशित किया की वे उपरोक्त योजनाओं में पूर्व निर्धारित राशि मे से शेष रही राशि सभी नगरीय निकायों को शीघ्र ही हस्तांतरित करें। उन्होनें रूडसिको के परियोजना निदेशक श्री सलामत अली, रूडसिको के सलाहकार श्री आर.के. अग्रवाल को निर्देशित किया की वे नगरीय निकायों में जाकर उपरोक्त योजनाओं के तहत बनाये जा रहे मकानों की स्थिति देखें तथा योजना के तहत नगरीय निकायों को आने वाली परेशानियों का मौके पर जाकर निस्तारण करें।

अमृत योजना में स्वीकृत कार्यो की समीक्षा

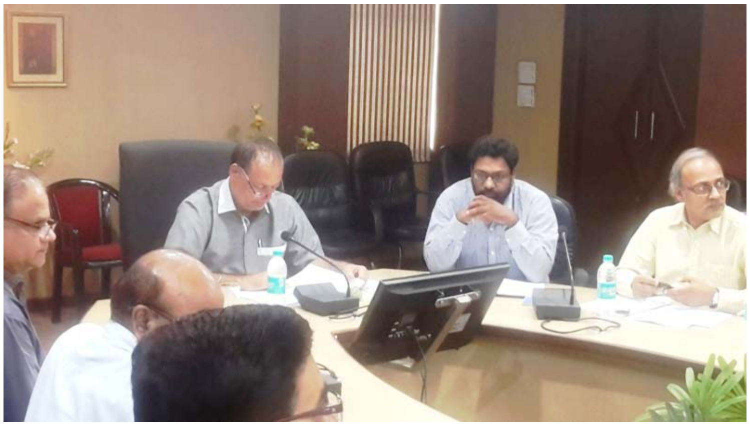

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में स्वीकृत कार्यो की गुरूवार को स्वायत्त शासन भवन में प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन डॉ मनजीत सिंह ने सभी अमृत शहरों को निर्देश दिये कि वे अमृत योजना के तहत स्वीकृत उद्यानों के निर्माण के दौरान सिविल कार्यो पर कम से कम व्यय करें तथा परियोजना में स्वीकृत राशि का उपयोग हरित क्षेत्रा विकसित करने में किया जाये। केन्द्र सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत निकाय क्षेत्रा में हरित क्षेत्रा विकास 15 प्रतिशत क्षेत्रा रखा गया है। उन्होनें योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि योजना के तहत अब तक 33 कार्यो को स्वीकृत किया गया है जिनमें से 16 कार्य सीवर परियोजना से संबंधित थे। जिनमें से 14 कार्यो की निविदा आमंत्रित कर स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। एक परियोजना निविदा के प्रक्रियाधीन है तथा एक कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। उन्होनें बताया कि योजना के तहत भरतपुर में 79.66 करोड़, चुरू में 98.37 करोड़, गंगापुर सिटी में 99.42 करोड़, हिण्डौन सिटी में 91.64 करोड़, नागौर में 60.02 करोड़, सुजानगढ़ में 100 करोड़, उदयपुर सिटी में 85 करोड़, बांरा में 85 करोड़, चित्तौड़गढ़ में 87.89 करोड़, ब्यावर में 109.91 करोड़, बून्दी में 100 करोड़ कुल 1286.54 करोड़ के कार्यो की स्वीकृती जारी की जा चुकी है। उन्होनें बताया कि योजना के तहत जलापूर्ति की 12 परियोजनाओं को स्वीकृती दी गई है। जिनमें से 6 परियोजनाओं ब्यावर, भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी, धौलपुर, सीकर, नागौर की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।

<u>प्रदेश की हर सिटी स्मार्ट सिटी हो यही हमारा उद्देश्य</u>

स्वायत्त शासन विभाग एवं स्मार्ट सिटी काउन्सिल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से (रेवेन्यू जनरेशन एण्ड प्रोक्यूरमेंट) कार्यशाला का आयोजन

प्रदेश की सभी नगरीय निकाय अपने–अपने संसाधनों से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे। प्रदेश की हर सिटी स्मार्ट सिटी हो यही हमारा उद्देश्य है।

प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने यह उद्गार शुक्रवार को स्वायत्त शासन भवन में स्वायत्त शासन विभाग एवं स्मार्ट सिटी काउन्सिल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित (रेवेन्यू जनरेशन एण्ड प्रोक्यूरमेंट) कार्यशाला में उपिस्थत नगरीय निकाय के अधिकारियों के समक्ष व्यक्त किये।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने इस अवसर पर कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब समझाते हुए कहा कि किसी भी शहर में वाटर सप्लाई ठीक हो पानी का नुकसान न हो 24 घन्टे नागरिको को पानी मिले, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर घर सीवरेज से जुड़ा हो, हर घर में टॉयलेट हो एव उसका उपयोग किया जाये। नगरीय निकायो द्वारा किये जाने वाले कार्य ऑन–लाईन हो, शहर का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन स्पेस विकसित हो, कचरे का प्रबन्धन हो।

उन्होने कहा कि राजस्थान की नगरीय जनसंख्या लगभग 5 करोड़ से अधिक है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश की हर नगरीय निकाय ऑन–लाईन हो तथा नागरिको को सभी आवश्यक मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हो। उन्होनें बताया कि वर्तमान में देश मे जारी केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं चाहे स्मार्टसिटी, एल.ई.डी. लाईट, अमृत स्वच्छ भारत मिशन हो सब में राजस्थान आगे है। प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में प्रोपर्टी का सर्वे किया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों मे दोहरी लेखा पद्धति से कार्य प्रारम्भ किया गया है। आने वाले समय में प्रदेश की 190 नगरीय निकाय क्षेत्रा में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर 40 हजार करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।

स्मार्ट सिटी काउन्सिल इंडिया के फाउण्डर डायरेक्टर श्री प्रताप पडोडे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी शहरों में योजनाओ को क्रियान्विति करने के लिये ैच्ट का गठन किया गया है। सभी स्मार्ट सिटी के अलग–अलग चेलेच्ज है। जिनका स्थानीय तरीके से निस्तारण कर नागरिको को उच्चस्तरीय जीवन उपलब्ध करवाना है। उन्होने कहा कि स्मार्ट सिटी देश के शहरो को विकसित करने का एक नया तरीका है।

कार्यशाला में जोधपुर नगर निगम आयुक्त ने पब्लिक ट्रांसर्पोटेशन के लिए अतिरिक्त बसो एवं उनकी फ्रिकवेन्सी बढ़ाने तथा फ्लाई ओवर निर्माण पर जोर दिया। अजमेर नगर निगम के कमिश्नर श्री डी.एस. पाण्ड्या ने कहा कि किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी सरकारी साधनो से नही बनाया जा सकता इसके लिये उस शहर की जनता को जोड़ा जाना अति आवश्यक है। उन्होने बताया कि स्मार्ट सिटी के प्रथम चरण में अजमेर इसलिये चयनित नहीं हुआ क्योंकि वहां स्मार्ट सिटी प्रस्तावो से जनता को नही जोड़ा गया। उन्होने बताया कि द्वितीय चरण में बनाये गये प्रस्तावो में हमने लगभग 3 लाख लोगों से सम्पर्क किया। लोगो ने अपने सुझावो में 48 प्रतिशत ने सेनिटेशन सुधार 47 प्रतिशत ने पब्लिक ट्रांन्सर्पोटेशन 47 प्रतिशत ने कचरा प्रबंधन पर तथा सेफ्टी सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई के संबंध में प्रस्ताव दिये है।

अब प्रदेश में भवन निर्माण स्वीकृती जारी होगी ऑन–लाईन

भिवाड़ी एवं उदयपुर की दो भवन निर्माण स्वीकृतियाँ जारी कर योजना का शुभारंभ

स्वायत्त शासन मंत्राी श्री राजपाल सिंह शेखावत ने मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे स्वायत्त शासन भवन में भवन निर्माण की प्रथम ऑन–लाईन स्वीकृती जारी की। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्राी श्री राजपाल सिंह शेखावत ने भिवाड़ी एवं उदयपुर की दो भवन निर्माण स्वीकृतियाँ जारी कर योजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना का 23 जून को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया था। योजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा 2 गोल्ड स्टार भी दिये गये थे। योजना को देश का सर्वोत्तम भवन निर्माण स्वीकृती सिस्टम माना गया है।

योजना के शुभारंभ के अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्राी श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि यह योजना आम नागरिकों को जहाँ एक ओर राहत प्रदान करेगी वहीं दूसरी ओर भवन निर्माण स्वीकृती में पूर्ण पारदर्शिता लागू होगी। उन्होनें कहा कि पूर्व में जहाँ भवन निर्माण स्वीकृती में अत्यधिक समय लगता था। अब भवन निर्माण स्वीकृती सामान्य प्रक्रिया में एक माह में तथा फास्ट ट्रेक स्वीकृती में एक दिन में जारी हो सकेगी तथा आवेदक भवन निर्माण स्वीकृती पर की जा रही कार्यवाही को ऑन–लाईन देख सकेगा। उन्होनें बताया कि ऑन–लाईन भवन निर्माण स्वीकृती की इस प्रक्रिया को नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की समस्त संस्थाओं, नगर निगम/पालिकाओं, सभी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों के साथ–साथ रीको को भी सम्मिलित किया गया है तथा पंचायती राज्य के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रक्रिया को लागू किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने इस अवसर पर बताया कि केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्राालय द्वारा हाल ही मे कराये गये एक अध्ययन के दौरान पता चला कि देश में भवन निर्माण स्वीकृती जारी करने में नगरीय निकायों को तीन माह से 2 वर्ष तक का समय लगता है। इससे जहाँ एक ओर आवेदन को परेशानी का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर देश में विकास की दर भी धीमी होती है। राजस्थान सरकार द्वारा इस और पहल की गई तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भवन निर्माण स्वीकृती के लिए एक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

उन्होनें बताया कि ऑन–लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम सिंगल विडों क्लियरेंस सिस्टम पर लागू किया गया है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्डिंग प्लान अप्रुवल से संबंधित समस्त प्रक्रिया को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। जिसमें बिल्डिंग प्लान का परीक्षण पत्राावली का आवेदन संबंधित नगरीय निकाय में पत्राावली का परीक्षण, विभिन्न शाखाओं के रिपोर्ट स्थल निरीक्षण, भवन मानचित्रा अनुज्ञा शुल्क एवं स्वीकृती जारी किये जाने की समस्त प्रक्रिया ऑन–लाईन किया गया है तथा जारी की गई स्वीकृती को आर्किटेक्ट, आवेदक एवं अन्य कोई भी व्यक्ति/संस्था ऑन–लाईन देख सकता है। उक्त सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के विकल्प निर्धारित किये गये है। पहला सामान्य एवं दूसरा

फास्ट ट्रैक रखा गया है तथा सॉफ्टवेयर में बिल्डिंग बॉयलॉज के 42 पैरामीटर निर्धारित किये गये है। फास्ट ट्रैक स्वीकृती में आवेदक (विकासकर्ता) को एक ही दिन में निर्माण स्वीकृती दी जा सकेगी। फास्ट ट्रैक स्वीकृती के तहत यदि भवन मानचित्रा बिल्डिंग बॉयलॉज के 42 निर्धारित मापदण्डों की पूर्ती करता है एवं भूमि स्वामित्व का एडवोकेट से प्रमाणित प्रमाण–पत्रा ऑन–लाईन प्रस्तुत करता है एवं निर्धारित राशि जमा कराता है, तो निर्माण स्वीकृती एक दिवस में जारी की जा सकेगी। सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदित आवेदनों पर एक माह में स्वीकृती जारी की जा सकेगी।

उन्होनें बताया कि उक्त प्रक्रिया में कोई भी कार्य मैन्यूअल नहीं हो सकेगा तथा साईट विजिट भी ऑन–लाईन मोबाईल के माध्यम से हो सकेगी। उक्त प्रक्रिया के लागू होने से भवन निर्माण स्वीकृती में पूर्ण पारदर्शिता आयेगी।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Contact Us

Local Self Government

Shri Rajpal Singh Shekhawat(Honorable Minister UDH)
(O)Ph No.+91141-2227533,

Shri Manjeet Singh(IAS) - Principal Secretary
Ph No. +91141-2227128

Shri Purushottam Biyani (IAS) Director and Joint Principal Secretary
Ph No.+91141-2222403
Fax: 0141-2222403

Call Center Toll free No.:- 1800-180-6127

Office-Local Self Government Department (Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur) G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur - Rajasthan -India